

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खब्द 3—उप-खब्द (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं∘ 30]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 1990/वीव 29, 1911

No. 30) N

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 1990/PAUSA 29, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकालन को रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विता संतालय

(फ्रानिक कार्यविभाग)

(विकास प्रमान)

अदेश

गई दिल्ली: 19 जनवरी: 1990

का. आ. 51(थ्र) वैककारी विनियमन ध्रधिनियम, 1919 (1939) का 10) की धारा 56 के खण्ड (यक्ष) के साथ पटिन धारा 15 की उपधारा (2) के हारा प्रदान णिवस्त्रों का प्रयाग करने हुए, केदीय सरकार उकत धारा 15 की उपधारा (1) के धंतर्गत भारतीय रिप्तर्थ वैंक हारा दिए गए धार्नेदन पढ़ पर विचार करने के बाद बांद्रा पीपन्त किआपरेटिव वैंक िए घांद्रा, सम्बर्ध-400050 (जिसे इसके पण्चात सिहकारी वैंक कहा गया है) के संबंध में एनदेद्राण 19 जनवरी, 1990 को थैक का कारोबार बंद होने से लेकर 19 मई, 1990 तक धार उस दिन की मिला कर अधिरयगन धादेश जारी करनी है, जिसके अनुसार प्रधिस्थान धादेश की प्रविध के दीरान सहकारी बैंक के विरुद्ध सभी कार्यक्षार्थों का एक किया जाना ध्रमवा श्रम्य की गई कार्यकाह्यों को जारी रुखना रुपिया रूपिया जाना द्रमवा स्वार्थ की यह है कि इस प्रकार के धीरस्थात का किया जाना है, किन्तु मने यह है कि इस प्रकार के धीरस्थात का विरुद्ध सीगाइटी

श्रक्षितियम 1960 के श्रंतर्गत महाराष्ट्र सरकार क्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उसके श्रधिकारों पर प्रतिकृत प्रभाव नहीं परें।

- 2. केन्द्रीय सरकार, एनद्द्रारा यह निदेण देती है कि स्थीकृत श्रीध-स्थान की श्रवधि के दौरान यह सहकारी बैंक, भोरतीय रिजर्य बैंक की लिखित पूर्वानुसनि के बिना कोई ऋण अथवा अधिम नहीं देगा, किसी श्रीयम का नदीकरण नहीं करेगा, बैंक की किसी परिसम्पत्ति का अस्य संक्रमण अथवा निपटान नहीं करेगा, किसी प्रकार का दाविस्थ रहीकार नहीं करेगा, किसी प्रकार का दाविस्थ रहीकार नहीं करेगा, कोई निवेण नहीं करेगा अथवा अपने दायित्यों और देत-दारियों के संबंध में अथवा अस्था किसी प्रकार की अवस्था नहीं करेगा अथवा श्रदायमी नहीं करेगा अथवा श्रदायमी करने. स्थोकार नहीं करेगा आयवा किसी प्रकार का समझौता अथवा टहराव नहीं करेगा किसी श्रदायमियों अथवा वहं करेगा :
- (1) प्रत्येक बनन केंक अथवा जानू खात अथवा किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले किसी अन्य जमा खाते की लेग रकम में से 250 रुपये में अनिधिक राशि, जिसमें 26 दिसम्बर, 1987 के बाद भुगनान की गई राशि यदि कोई हो, शामिल है, करने हुए बशार्ते कि अदा की गई रकम की कुल सीमा किमी एक व्यक्ति (किसी अन्य व्यक्ति के माथ संयुक्त खाने में नहीं) के नाम से खाने में जमा कुल राशि 250/- रुपये में क्यादा न हो.

यह भी शर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई रक्षम ग्रदा नहीं की जाएनी जो किसी प्रकार से सहकारी बैंक का कर्जवार हो;

- (2) ऐसे किसी हैंक कुपर, पेकाईर स्थया वैधे की शिण जी सहकारी बैंक द्वारा 26 दिसम्बर् 1987 हो आर्री कर दिए गए है, और जिनका उस नारीक व्यव भूगरान नहीं किया गया है, जिसकी अधिस्थान श्रादेण लागू होना है।
- (3) 26 दिसम्बर, 1987 को अथवा उससे पूर्व भ्रुगतान के लिए प्राप्त हुंडियों की राशि चाहे वे उस तारीक से पहले, उस तारीक को या उस सरीक के बाद बसूल की गई हों।
- (4) ऐसा कोई ज्यय जो किसी सहकारी बैंक के द्वारा उसके अथवा उसके विरुद्ध दायर किए गए मुकदमे, अधील अथवा महकारी बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध ली गई डिक्री या बैंक की मिलते थाली किसी रकम को बसूल करने के संबंध में करना प्रावश्यक हो, बलने कि प्रत्येश मुकदमे. अपील अथवा डिक्री के संबंध में किए जाने बाले ज्या की रक्षम 600/- रुपए से अधिक हो, तो खर्च करने से पहले भारतीय रिजर्य बैंक का लिखित अन्मित ली जाएगी:
- (5) ऐसा कोई व्यय जो शिक्षा, बीसा ग्रीर प्रत्यय गारंटी निगम की देय प्रोमियम की अधि हो; ग्रीय
- (6) किसी धन्य मद पर कोई व्यय, जहां तक कि वह गय सहकारी बैंध के विचार में बैंक का दैनिक प्रणासन चयाने के लिए करना अति-वार्यहो।

बशर्ते कि जहां किया। एक कैलेण्डर माम में किसी मद पर किया गया कुल खर्च अधिस्थान आदेश में पहले के छा कैलेण्डर महीतों में उस मद पर किए गए औसत गामिक व्यय में बढ़ जाता हो, अथबा उसे अविध के दौरान कहां उस मद पर कोई व्यय नहीं किया गया हो औं उस प्रकार किया जाने बाला व्यय 250/- रुपये से बढ़ जाए तो उस प्रकार का व्यय करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंग की लिखिन वय में अनुमति की जाएगी।

- 3. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह भी निवेश देनी है कि सहकारी बैंक की स्वीकृत अधिस्थान की श्रविध के धौरान:
- (क) यह सहकारी बैंश निम्नलिखिन और अवायिनियों कर सकेना अवासि सरकारी प्रतिभृतियों अथवा अन्य प्रतिभृतियों के बदी महाराष्ट्र सरकार अथवा मताशिक सेंक लि. या टाणें कि ही सहाराष्ट्र सरेट की आपरेटिव एपेक्स बैंक लि. या टाणें कि ही सर सेंक कि. या टाणें अथवा भारतीय स्टेट वैक अथवा इसके किन्ही सहायों बैंकों या किसी अन्य बैंके द्वारा महनारी बैंक को किए गए ऋणों अथवा अधिकों, जो अधिस्थान आदेश के प्रभावी होने की निए गए ऋणों अथवा अधिकों, जो अधिस्थान आदेश के प्रभावी होने की निए साथवा होने की निए अध्यापक हो।
- (ख) सहकारी यैंदे को पूर्वोका श्रदःयगियां करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट कोन्नापरेटिक एपेक्स बैका लि. श्रवका किसी श्रव्य श्रेक के साथ श्रवक खाते चलाने की श्रवसित दी जाएगी।

परंतु इस आदेश का ऐसा कोई आश्रय नहीं होगा कि इस बैक सहरारं को किसी रवस के दिए जाने से पहले सहाराष्ट्र रटेट की-आपरेटिव एपेक्स बैक लि. अथवा वैसे किसी अन्य बैंक को इस संबंध में अपने आपको आध्वस्त करना होगा कि इस आदेश द्वारा लगाई गई शनों का इस बैंक द्वारा पालन किया आ रहा है।

(ग) यह सहकारी बैंक, उन हुंडियो को, जो बसूल न की गई हो. उनको प्राप्त करने के हकदार ध्यक्ति के श्रनुरोध पर गौटा सकेगा यदि इस सहकारी बैंक का उन हुंडियों पर कोई प्रक्षिकार श्रथ्या हक न हो अथवा बैंसी हुंडियों में उसका कोई हिन न हो।

- (घ) महकारी बैंक ऐसे माल श्रवका प्रतिभूतियों को जो इस (बैंक) के पास किस। ऋषा, तकटी, का श्रवका भीवर हास्ट के बदले गिर्फा, इस्टि २५ से अथवा श्रवका ग्रवका ग्रवका प्रतिकार के वें के वें के वें के प्रतिकार के के बदले गिर्फा, इस उपने के प्रतिकार के के बदले ग्रिका के प्रतिकार के विकास के प्रतिकार के
 - (1) किसी ऐसे मामले में जहां यथास्पित ऋगगनीकों से मितने बाली सारी रुकम सहकारी धैक द्वारा क्यिना धर्न प्राप्त को गर्द है; श्रीर
 - (2) किसी अन्य मामले में, उस मीमा तक की रक्तम जिनती आव-ण्यक अथवा सम्भव ही, निदिष्ट अनुपानों में नीचे अप्यक्ष उन अनुपानों से मीचे, जो अधिस्थान आदेण के प्रभायी होने से पहले लागू थी, इनमें जो भा ऊंबे हीं, उक्त माल और प्रति-भूतियो पर मार्जिन के अनुपानों को कम किए बिना।

[एए सं. 6-4/89 ए जी]

प्रतीण कुमार तेजपान, प्रापर संविक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

ORDER

New Delhi, the 19th January, 1990

- 5.O. 51(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45, read with clause (zb) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering the application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of the said section 45, hereby makes an order of moratorium in respect of the Bandra People's Co-operative Bank Ltd., Bandra, Bombay-400 050 (hereinafter referred to as the Co-operative Bank) for the period from close of business on the January 19, 1990 upto and inclusive of the May 19, 1990 staying the commencement or continuance of all actions and proceedings against the Co-operative Bank during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Government of Maharashtra of its powers under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.
- 2. The Central Government hereby directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank shall not, without the prior permission in writing of the Reserve Bank of India, grant any loan, make or renew any advance, alienate or dispose of any assets of the said Bank, incur any liability, make any investment or make or agree to make any payment, whether in discharge of its liabilities or obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except making of payments, or incurring of expenditure, as the case may be, to the extent and in the manner provided hereunder:—
 - (i) Out of the balance in every savings bank or current account or in any other deposit account, by whatever name called, a sum not exceeding Rs. 250 including the amount, if any, paid after 26th December. 1987.

Provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 250;

Provided further that no amount shall be paid to any depositors who is indebted to the Co-operative Bank in any way:

- (ii) the amounts of any drafts or pay orders or cheques issued on or before 26th December 1987 by the Co-operative Bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;
- (iii) The amounts of the bills received for collection on or before 26th December 1987 whether realized before, on or after that date:
- (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suitsor appeals filed by or against, or decrees obtained by or against, the Co-operative Bank, or for realizing any amounts due to it;

Provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree is in excess of Rs. 600\(\), the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred;

- (v) the amount of premium payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation; and
- (vi) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the Cooperative Bank necessary for carrying on the day-to-day administration of the Cooperative Bank:

Provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds the sum of Rs. 250]-, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

- 3. The Central Government hereby also directs that, during the period of moratorium granted to it, the Co-operative Bank—
 - (a) may make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying

loans or adavnces granted against Government securities or other securities to the Co-operative Bank by the Government of Maharashtra or the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or Bombay District Central Co-operative Bank Ltd., or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

(b) may operate its accounts with the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or with any other bank for the purpose of making the payments aforesaid;

Provided that nothing in this order shall be deemed to require the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or such other bank to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Co-operative Bank:

- (c) may return any bills which have remained unrealized to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the Co-operative Bank has no right or title to, or interest in such bills;
- (d) may release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft, in the maner and to the extent—
 - (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the Co-operative Bank, unconditionally, and
 - (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions, or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[F. No. 6-4'89-AC]

P. K. TEJYAN, Under Secv.

•	